

[2023] 11 एससीआर 652:2023 आई. एन. एस. सी. 766

मुकदमों का विवरण

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम

ए. जी. डी. रेड्डी

(2011 की सिविल अपील सं. 11196) 24 अगस्त, 2023

[जे. के. माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या डिवीजन बेंच और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 49 (ई) के तहत परिकल्पित "स्केल-1 में मूल वेतन में कमी" के दंड को लागू करने वाले नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में न्यायसंगत ठहराया गया था और अपराधी अधिकारियों द्वारा बिताए गए समय को उनकी बहाली की तारीख तक 18.08.1990 से निलंबन के तहत केवल निलंबन के रूप में माना गया था।

सेवा कानून-कदाचार-बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम करते समय कर्मचारी द्वारा किए गए कुछ कदाचार के कृत्य-अनुशासनात्मक कार्यवाही-नियुक्ति प्राधिकरण ने स्केल-1 में मूल वेतन में कमी का दंड लगाया और दोषी अधिकारी द्वारा अपनी बहाली की तारीख तक निलंबन के तहत बिताई गई अवधि को केवल निलंबन माना-एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आदेश को रद्द कर दिया-सच्चाई:

आयोजित किया गया: एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ दोनों ने जांच कार्यालय के निर्णय, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय और नियुक्ति प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने में गलती की-इस प्रकार, एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेश को अपास्त करना दिया गया-भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियम - आर. 49 (ई)।[पैरा 41]

सेवा कानून-अनुशासनात्मक कार्यवाही-सबूत की जिम्मेदारी:

652 653

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी 654

आयोजित किया गया: अनुशासनात्मक कार्यवाही में, सबूत का भार आरोप की प्रकृति और कर्मचारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की प्रकृति पर निर्भर करता है-किसी दिए गए मामले में, स्पष्टीकरण के आधार पर बोझ कर्मचारी पर स्थानांतरित किया जा सकता है-तथ्यों पर, निर्दिष्ट सी शुल्क नामित इकाइयों की एक श्रृंखला के संबंध में था, आवधिक निरीक्षण नहीं किए गए थे-निरीक्षण रजिस्टर पेश करने के बाद ही कर्मचारी के बचाव प्रतिनिधि ने कहा था कि वे उक्त

दस्तावेजों को देखने के बाद जवाब देंगे-कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी-न तो रिकॉर्ड से और न ही सुनवाई पर यह प्रदर्शित किया गया था कि निरीक्षण करने में विफलता के आरोप का कर्मचारी द्वारा कैसे विरोध किया गया था-उपलब्ध कराए जाने वाले रिकॉर्ड, यह दिखाने के लिए कर्मचारी पर स्थानांतरित किया गया था कि आरोप था[पारस 22-25]

सेवा कानून-अनुशासनात्मक कार्यवाही-न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र:

[illegible]

[illegible]

सअपीलार्थी कअपीलार्थी तअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी
अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी ंअपीलार्थी
चअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी पअपीलार्थी ोअपीलार्थी रअपीलार्थी
्अपीलार्थी टअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी नअपीलार्थी ुअपीलार्थी
शअपीलार्थी ाअपीलार्थी सअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी
मअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी
धअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी
ीअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी ंअपीलार्थी चअपीलार्थी अपीलार्थी
औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ुअपीलार्थी
कअपीलार्थी ्अपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी
रअपीलार्थी ाअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी
अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी आअपीलार्थी दअपीलार्थी ेअपीलार्थी
शअपीलार्थी ।अपीलार्थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

न्यायाधीश और खंड पीठ जांच की कार्यवाही और लगाई गई सजा को दरकिनार करने में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए टिकाऊ नहीं हैं।[पारस 32,33,36 और 37]

सेवा कानून-दंड-आरोपों की गंभीरता-दंड के आदेश में हस्तक्षेप:

आयोजित किया गया:यदि किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में, साबित किए गए आरोपों पर दंड का आदेश लगाया जा सकता है और उन आरोपों पर लगाया गया दंड कानूनी रूप से टिकाऊ है, तो यह न्यायालय के लिए इस बात पर विचार करने के लिए नहीं है कि क्या केवल उन आधारों ने सजा देने में प्राधिकरण को प्रभावित किया होगा-जब तक कि लगाया गया दंड केवल उन आरोपों में से किसी के साथ सह-संबंधित नहीं है जो साबित नहीं हुए हैं, तब तक दंड को दरकिनार नहीं किया जा सकता है-तथ्यों पर, सजा तब भी कायम रखी जा सकती है जब तक कि साबित नहीं किए गए आरोप अपास्त करना हो जाते हैं-परीक्षण नुकसान का परिणाम नहीं है या लाभ नहीं किया गया है, परीक्षण यह है कि क्या अपराधी कर्मचारी ने बैंक के निर्धारित मानदंडों का पालन किया है-लगाया गया दंड "स्केल-1 में सबसे कम स्तर तक मूल वेतन में कमी" है और आगे, अवधि का इलाज करने के लिए।[पैरा 41]

उड़ीसा राज्य बनाम बिद्याभूषण महापात्रा [1963] 1 पूरक।एस. सी. आर. 648; उप
महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) और अन्य।वी. अजय कुमार

श्रीवास्तव (2021) 2 एस. सी. सी. 612-पर भरोसा किया।

नंद किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य (1978) 3 एस. सी. सी. 366:[1978] 3
एससीआर 708; अनिल कुमार बनाम पीठासीन अधिकारी और अन्य (1985) 3

एससीसी 378-प्रतिष्ठित।

उड़ीसा खनन निगम और एक अन्य बनाम आनंद चंद्र पृष्टि

(1996) 11 एससीसी 600:[1996] 8 पूरक।एस. सी. आर. 433; भारतीय स्टेट बैंक
बनाम राम लाल भास्कर और एक अन्य (2011) 10 एस. सी. सी. 249:[2011] 12
एससीआर 1036; ए. पी. बनाम राज्यएस. श्री रामाराव ए. आई. आर. 1963 एस. सी.
1723:

[1964] एससीआर 25; अनुशासनात्मक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी 656

655

प्राधिकरण सह क्षेत्रीय प्रबंधक और अन्य बनाम निकुंजा बिहारी पटनायक,

(1996) 9 एससीसी 69:[1996] 1 पूरक।एस. सी. आर. 314-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2011 की सिविल अपील सं. 11196।

2003 के डब्ल्यू. ए. सं. 8085 में बेंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक
20.10.2010 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

संजय कपूर, सुश्री महिमा कपूर, सूर्य प्रकाश, अर्जुन भाटिया, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एस. एन. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता, तरुण कुमार ठाकुर, डी. पी. चतुर्वेदी,

सुश्री पार्वती भट, सुश्री अनुराधा मुतातकर, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

के. वी. विश्वनाथन जे.

1. भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान अपील (संक्षेप में "बैंक"), 2003 की रिट अपील संख्या 8085 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 20.10.2010 के फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाती है। उक्त निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने बैंक की अपील को खारिज कर दिया था और विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 12.11.2003 के निर्णय और आदेश को स्वीकार कर लिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के नेतृत्व में 1997 की रिट याचिका संख्या 29547 को अनुमति दी थी और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था और प्रत्यर्थी को परिणामी लाभ प्रदान विद्वान था। नियुक्ति प्राधिकरण ने अपने आदेश 31.01.1995 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 49 (ई) के तहत परिकल्पित "स्केल-1 में सबसे निचले स्तर तक मूल वेतन में कमी" का दंड लगाया था और इसके अलावा, दोषी अधिकारियों द्वारा 18.08.1990 से उनकी बहाली की तारीख तक निलंबन के तहत बिताई गई अवधि को केवल निलंबन के रूप में माना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

2. व्यथित होने के कारण बैंक ने वर्तमान अपील का नेतृत्व किया है। बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कपूर का तर्क है कि अवर न्यायालयों ने न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का उल्लंघन किया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अवर न्यायालयों ने अनुशासनात्मक अधिकारियों के आदेशों को विकृत के रूप में चिह्नित करने में गलती की है।

3. इसके विपरीत, श्री एस. एन. भट द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रत्यर्थी, विद्वान वरिष्ठ वकील, विवादित आदेशों का जोरदार बचाव करते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि वर्तमान "कोई सबूत नहीं" का मामला था और बिना किसी सबूत के और केवल उनके व्यक्तिगत कथित ज्ञान के आधार पर आधिकारिक जांच में अपराध की स्थिति दर्ज की गई है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देते हैं कि अवर न्यायालयों ने अनुशासनात्मक अधिकारियों के आदेश को सही ढंग से अपास्त करना दिया है और मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

प्रासंगिक तथ्य

4. तथ्य, जहाँ तक वे इस अपील के निर्णय के लिए आवश्यक हैं, नीचे दिए गए हैं:

क) प्रत्यर्थी के खिलाफ कथित रूप से किए गए कदाचार के कुछ कृत्यों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी जब वह बैंक की महादेवपुरा शाखा के फील्ड अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। मोटे तौर पर, दिनांकित 13.02.1992 आरोप पत्र में आरोप थे:

i) कि उन्होंने शाखा प्रबंधक से अनुशंसा की और स्वीकृति प्राप्त की, विभिन्न इकाइयों के लिए क्रेडिट सीमा, जैसा कि उसमें विस्तृत है और निरंतर आधार पर अतिरिक्त ड्रॉइंग की अनुमति दी; कि उन्होंने अनुमति प्राप्त अतिरिक्त ड्रॉइंग के बारे में नियंत्रक कार्यालय को सूचित नहीं किया; कि उन्होंने मौजूदा निर्देशों के अनुसार आवधिक निरीक्षण नहीं किया; कि ऋण मंजूरी दी गई थी और

किसी अन्य इकाई के परिसर में काम करने वाली संस्थाओं को क्रेडिट सीमा का विस्तार किया गया था; (ii) उस ऋण सीमा की सिफारिश की गई थी और मेसर्स सरस्वती फैब्रिकेटर्स के लिए मंजूरी प्राप्त की गई थी, भले ही इकाई संचालन के क्षेत्र से दूर स्थित थी; अग्रिम मंजूरी की सूचना नियंत्रक कार्यालय को नहीं दी गई थी; और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक बनाने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं;

iii) कि प्रत्यर्थी ने मेसर्स एसीई फोटो रिप्रोग्राफर्स और मेसर्स संगीता रिफ्रेशमेंट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी को अग्रिम राशि की मंजूरी की सिफारिश की और प्राप्त की।

657

[के. वी. विश्वनाथन, जे.]

शिवाजीनगर से दोनों, भले ही इकाइयाँ अस्तित्व में नहीं थीं और प्रस्तुत किए गए विवरण वास्तविक थे क्योंकि एक अन्य एफ. आई. आर. एम. मेसर्स ऑल आर्ट्स कंपनी उसी परिसर से काम कर रही थी; कि इन अग्रिमों की मंजूरी की सूचना नियंत्रक कार्यालय को नहीं दी गई थी और इकाइयों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया था।

(iv) कि प्रत्यर्थी ने मेसर्स राजेश्वरी एंटरप्राइजेज को 20.05.1987 नकद क्रेडिट सीमा पर मंजूरी की सिफारिश की थी और प्राप्त की थी और प्रत्यर्थी ने नियंत्रण विवरणी जमा नहीं की थी; कि आवधिक निरीक्षण नहीं किए गए थे और सीमा की मंजूरी के लिए पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित अचल संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक बनाने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं। निर्धारित कुछ अन्य आरोप, जो अपील के निर्णय के लिए सीधे प्रासंगिक नहीं हैं, को यहाँ ऊपर उजागर नहीं किया गया है।

v) आरोप पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि किए गए कार्यों द्वारा, प्रत्यर्थी अग्रिमों की मंजूरी और अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में मौजूदा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा और बैंक के हितों को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए सभी संभव कदम उठाने में विफल रहा और अपने कर्तव्यों का अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी के साथ निर्वहन नहीं किया और इस तरह सेवा नियमों का उल्लंघन किया।

ख) आरोप के हिस्से के रूप में, यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अक्टूबर 1987 में आईडी1 एकड़ के हिसाब से कृषि भूमि खरीदी और मेसर्स बिंदु एंटरप्राइजेज के श्री राममूर्ति, जो शाखा में ऋण सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, के निवेश का उपयोग करके इसे मामूली राशि के लिए अपने नाम पर पंजीकृत कराया और वह बैंक को मौजूदा निर्देशों के अनुसार अचल संपत्ति की खरीद की घोषणा करने में विफल रहे। यह आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त कृत्यों द्वारा, उन्होंने खुद को पार्टी के प्रति आर्थिक दायित्वों के तहत रखा।

ग) आरोपों के बयान भी प्रस्तुत किए गए थे।

पूछताछ कार्यालय के निष्कर्ष

5) प्रत्यर्थी ने आरोपों से इनकार करते हुए अपना विस्तृत जवाब दिया। एक पूछताछ अधिकारी नियुक्त किया गया था। पूछताछ कार्यालय से पहले, बैंक ने सात गवाहों से पूछताछ की और चौबीस दस्तावेजों को चिह्नित किया। अपराधी कर्मचारी ने किसी गवाह से पूछताछ नहीं की, लेकिन तीस दस्तावेज पेश किए। जाँच अधिकारी ने जाँच की कार्यवाही पूरी करने के बाद, सभी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और प्रत्यर्थी को लगाए गए कुछ आरोपों के लिए दोषी पाया और 658 को दोषमुक्त कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

कुछ अन्य आरोपों के संबंध में प्रत्यर्थी। प्रस्तुतकर्ता ऑफिसर ने आरोप पत्र में निहित निम्नलिखित आरोपों को आगे नहीं बढ़ाया।

- “(क) मेसर्स फोटोग्राफी के. एस. के संबंध में प्रभारित ऑफिशियल द्वारा ऋण की सिफारिश।
- (ख) प्रभार VII (ख)-इकाई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एवेन्यू रोड, बेंगलूर से ऋण लिया था।
- (ग) प्रभार II-मेसर्स बिंदु एंटरप्राइजेज के श्री राममूर्ति द्वारा 21.36 एकड़ भूमि की खरीद और पंजीकरण के लिए निवेश।”

निम्नलिखित आरोप साबित नहीं हुए:

- “I. इन इकाइयों के संबंध में मेसर्स फारुक टैनिंग कंट्रोल फॉर्म से संबंधित आरोप संख्या (ii) (ए) प्रस्तुत किए गए थे।
- II. मेसर्स फोटोग्राफी के. एस. के मामले में अनुमति प्राप्त अतिरिक्त चित्रों की सूचना न देना।
- III. मेसर्स एस फोटो रिप्रोग्राफर्स

यह आरोप कि इकाई काम नहीं कर रही है, साबित नहीं हुआ है।” शेष आरोप साबित हुए।

6) इन तथ्यों के साथ, जाँच अधिकारी ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट दिनांकित 23.08.1993 और जाँच के रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ दूसरा कारणदर्शक नोटिस जारी किया, जिस पर प्रत्यर्थी ने एक विस्तृत जवाब दिया। इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने पूछताछ कार्यालय के निर्णय के संबंध में असहमति के बिंदुओं को निर्धारित करते हुए दिनांक 04.10.1993 पर एक नोटिस भी जारी किया, जिस पर प्रत्यर्थी ने फिर से जवाब दिया।

अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्ष और जुर्माना लगाना

7) अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अपने 28.12.1994 के आदेश से इस मामले पर विस्तार से विचार किया। वह जांच अधिकारी के सभी पहलुओं से सहमत थे और यहां तक कि उन पहलुओं पर भी जहां जांच अधिकारी ने माना कि आरोप साबित नहीं हुए थे, अनुशासनात्मक कार्यवाही अलग-अलग 659 थी।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 660 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

उन पहलुओं में से कुछ पर आधिकारिक जांच के साथ और आरोपों को साबित करने के लिए अभिनिर्धारित किया।

उदाहरण के लिए, एक इकाई-एसीई फोटो रिप्रोग्राफर्स के परिसर में काम नहीं करने के मामले में, जबकि जांच अधिकारी ने आरोप को साबित नहीं किया, अनुशासनिक प्राधिकरण ने आरोप को साबित करने के लिए माना।

8) इन पहलुओं को न्यायालय को और अधिक रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि नीचे दी गई चर्चा से स्पष्ट होगा, अंततः प्रभार में उल्लिखित इकाइयों का आवधिक निरीक्षण नहीं करने के संबंध में आरोप और मैसर्स सरस्वती फैब्रिकेटर के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक बनाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा न करना प्राथमिक पहलू हैं जिन्होंने इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। जैसा कि इस निर्णय के बाद के भाग में चर्चा से स्पष्ट होगा, यह वे दो आरोप हैं जो अंततः साबित हुए हैं जिन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है।

9. उपरोक्त के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकरण ने भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम संख्या 49 (ई) के तहत प्रदान किए गए "स्केल-1 में सबसे निचले स्तर तक मूल वेतन में कमी" का जुर्माना लगाने के लिए 31.01.1995 पर एक आदेश पारित किया और आगे उसकी बहाली के आदेश तक 18.08.1990 से निलंबन की अवधि को केवल निलंबन के रूप में माना।

10. जिस अपीलीय प्राधिकरण से प्रत्यर्थी ने संपर्क किया, उसने आदेशों को स्वीकार कर लिया।

11. अनुशासनात्मक प्राधिकरणों और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए, याची ने एक रिट याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप अब विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेश आ गए हैं।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रभार I के तहत सामान्य प्रमुखों को वर्गीकृत विद्वान जैसा कि पूछताछ कार्यालय द्वारा भी विद्वान गया था

(i) आवधिक निरीक्षण का संचालन;

(ii) नियंत्रण प्रपत्र जमा न करना और (iii) संचालन का क्षेत्र।

13. हम सुविधा के लिए दूसरे और तीसरे अंगों पर विचार करने के बाद पहले अंग से निपटेंगे।

नियंत्रण प्रपत्र जमा न करने और संचालन के क्षेत्र के संबंध में प्रभार

14. नियंत्रण प्रपत्र जमा न करने के पहलू पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलिखित विद्वान कि प्रत्यर्थी पर बोझ गलत तरीके से स्थानांतरित विद्वान गया था जब पूछताछ कार्यालय ने अभिनिर्धारित विद्वान कि अपराधी ने नियंत्रण प्रपत्र जमा करने को साबित नहीं विद्वान था। विद्वत एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित विद्वान कि जब प्रत्यर्थी आरोप से इनकार करता है, तो प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करके अपराधी कर्मचारी के खिलाफ कथित आरोप को साबित करने की जिम्मेदारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण पर होती है और सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि यह कर्मचारी के अपराध को साबित करने के बराबर हो।

15. हमने इस मुद्दे पर पूछताछ रिपोर्ट का अध्ययन विद्वान है और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस मामले में सही हैं। जाँच रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य इस निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं:-

“हालाँकि, नियंत्रण प्रपत्र जमा न करने के संबंध में आरोप पत्र में सूचीबद्ध अन्य इकाइयों के संबंध में आरोप साबित होते हैं। हालाँकि, यह संभावना है कि शाखा के स्थानांतरण के कारण बैंक का शुल्क गायब हो सकता है, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा नियंत्रण प्राधिकरण से नियंत्रण प्रपत्र लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह केवल स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नियंत्रण प्रपत्र जमा नहीं किए गए हैं। यह आरोपित अधिकारी की ओर से विफलता है।”

16. समान रूप से तीसरे अंग के संबंध में, अर्थात् संचालन के क्षेत्र के उल्लंघन के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही पाया कि कई मामलों में ऋण संचालन के क्षेत्र के बाहर स्वीकृत किए गए थे और इस तरह, यह नहीं माना जा सकता था कि अपराधी प्रत्यर्थी द्वारा कोई उल्लंघन विद्वान गया था। जब हम जांच रिपोर्ट पर गौर करते हैं तो यह दृष्टिकोण स्वतंत्र रूप से स्पष्ट होता है।

17. "संचालन का क्षेत्र" शीर्ष के तहत प्रारंभिक पैराग्राफ में, बैंक के सापेक्ष निर्देशों से निपटने के दौरान, निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

“ii) जहां संबंधित परिचालन क्षेत्र के बाहर स्थित योग्य इकाइयों के समूह हैं, चाहे वे एसएसआई हों या लघु व्यवसाय, उन्हें सहायता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते वह स्थान पूरे वर्ष सुलभ हो और सार्वजनिक परिवहन द्वारा जुड़ा हो। ऐसे मामलों में भी, 661

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 662

इकाइयों का स्थान परिचालन क्षेत्र से बहुत दूर नहीं होना चाहिए और इकाइयों की संख्या यथोचित रूप से बड़ी होनी चाहिए। (sic.) इस संबंध में सिफारिशें पहले नियंत्रक प्राधिकरण से

अनुमोदित होनी चाहिए। 3. गोद लिए गए गाँवों में एस. एस. आई. और छोटी व्यावसायिक इकाइयों को ऋण देना भी नियंत्रक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है। (iv) हालांकि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से छिटपुट ऋण न मिले। इकाइयों/विकास केंद्रों के समूहों के विकास के लिए बेहतर दृष्टिकोण होना चाहिए।”

जाँच रिपोर्ट या साक्ष्य में कहीं भी यह सामने नहीं आया था कि अपवादात्मक श्रेणियों में उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया गया था।

आवधिक निरीक्षणों के संचालन के संबंध में प्रभार

18. तथापि, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्वत एकल न्यायाधीश और खंड पीठ, जिसने विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश को स्वीकार विद्वान था, ने प्रथम अंग के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दर्ज करने में गलती की, अर्थात्, प्रत्यर्थी द्वारा वर्तमान निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार आवधिक निरीक्षण नहीं करने के बारे में:-

“जहाँ तक आरोप के पहले घटक का संबंध है, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि जांच से पहले बैंक द्वारा जांचे गए गवाहों में से किसी ने भी आरोप ज्ञापन में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा के बारे में बात नहीं की है। हालांकि, जांच अधिकारी ने अपनी लंबी रिपोर्ट में बैंक के फील्ड अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के संचालन के लिए बैंक के प्रमुख अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहा कि यह फील्ड अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे आवधिक निरीक्षण करें और उन निरीक्षणों के उचित रिकॉर्ड बनाए रखें। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपराधी अधिकारी इस आरोप के लिए दोषी है, वह केवल अपनी रिपोर्ट में कहता है कि श्री कृष्ण मूर्ति उराला-अभि. साक्षी 4 ने बयान दिया है कि आरोपित अधिकारी ने कोई आवधिक निरीक्षण नहीं किया है। जाँच अधिकारी का यह निष्कर्ष जाँच अधिकारी द्वारा पीडब्लू-4 के साक्ष्य के गलत अध्ययन पर आधारित है। वास्तव में, अभि. साक्षी 4 ने जांच अधिकारी के समक्ष अपने लंबे अभिसाक्ष्य में कहा है कि इकाइयों का आवधिक निरीक्षण याची द्वारा कभी स्वतंत्र रूप से और कभी शाखा प्रबंधक के साथ किया जाता था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

और संबंधित अभिलेख शाखा में उपलब्ध नहीं थे। यह भी सबूत में आया है कि शाखा को वर्ष 1989 में किसी समय नए भवन में स्थानांतरित किया गया था और स्थानांतरण के दौरान, इकाइयों के निरीक्षण की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली किताबें गलत हो सकती हैं और उनका थोड़ा पता लगाया जा सकता है। इसलिए, मेरी राय में पी. डब्ल्यू. 4 के अभिसाक्ष्य में इधर-उधर एक छिटपुट वाक्य को चुनना और बैंक द्वारा जारी तथाकथित निर्देशों और दिशानिर्देशों के बारे में अपनी व्यक्तिगत जानकारी का हवाला देते हुए, मेरे विचार में, जांच

अधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते थे कि याची आवधिक निरीक्षण करने में विफल रहा और इसलिए आरोप ज्ञापन में आरोप का वह हिस्सा उसके खिलाफ साबित होता है।”19. इस पहलू पर खुद को संतुष्ट करने के लिए, हमने जांच रिपोर्ट की जांच की। निरीक्षण के लिए तर्क रिपोर्ट के प्रारंभिक भाग में निर्धारित किया गया है। इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है:-

“सावधि ऋणों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई और पर्यवेक्षण:

विशेष रूप से लघु इकाइयों को सावधि ऋण देना, ऋण की लंबी अवधि के कारण विभिन्न जोखिमों के अधीन है और इस तथ्य के कारण कि लघु इकाइयां वित्तीय रूप से कमजोर होने के कारण उनके भाग्य में मामूली प्रतिकूल परिवर्तनों से भी प्रभावित होने की संभावना है, जहां अचल संपत्तियों का बंधक प्राप्त किया जाता है, हम अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं, हालांकि चूक की स्थिति में प्राप्ति की प्रक्रिया भारी साबित हो सकती है। हालांकि, जहां प्रतिभूति में पट्टे पर दिए गए, किराए के परिसर में मशीनरी शामिल है, जोखिम बहुत अधिक हैं; चल मशीनरी, विशेष रूप से, घोर हटाने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, किराए के परिसर में किरायेदारी को मालिक द्वारा समाप्त करने की मांग की जा सकती है, हालांकि कानून आम तौर पर किरायेदारी को अनुचित निष्कासन से बचाता है।

पूर्वगामी विचार को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के उचित चयन को जोड़ना एक ऐसी बात है जिस पर काफी विचार किया जाना चाहिए। वन संरक्षण और संभावित नुकसान से बचने का एकमात्र साधन ऋण दिए जाने के बाद सतर्क अनुवर्ती कार्रवाई करना होगा।”

इसके बाद कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। आरोप से निपटने के लिए, पूछताछ कार्यालय निम्नलिखित को दर्ज करता है:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 664

- 663

“उपरोक्त निर्देशों से यह देखा जा सकता है कि समय-समय पर निरीक्षण करना और उन निरीक्षणों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना फील्ड ऑफिस का कर्तव्य है।

बचाव पक्ष ने केवल इस दलील पर आरोप का विरोध किया कि साक्ष्य के लिए निरीक्षण रजिस्टर पेश नहीं किया गया है। आई को न केवल निरीक्षण रजिस्टर को बनाए रखना है, बल्कि अलग से रिपोर्ट के माध्यम से निरीक्षण के दौरान अपने (एस. आई. सी.) द्वारा की गई टिप्पणियों की रिपोर्ट भी करनी है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी कोई भी रिपोर्ट यह साबित करने के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा निरीक्षण किए गए हैं।

इस संबंध में वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के संबंध में बैंक के निम्नलिखित निर्देश लाना उचित है। 2 लाख रुपये और उससे अधिक के उधार वाले खातों को। (STF6) के लिए एक प्रोफार्मा चिह्नित अनुवर्ती प्रपत्र के आधार पर। द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। प्रपत्र में अंतर्निहित उद्देश्य निरंतर आधार पर गतिविधि स्तर से बकाया को जोड़ना है,

यानी हर महीने, और गतिविधि स्तर को पहले के अनुमानों से जोड़ना है (जैसा कि योजना या पिछले प्रदर्शन के आधार पर अनुमानों में संकेत दिया गया है)। इस प्रपत्र के माध्यम से एक व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई किसी खाते में अनियमितता के प्रति किसी भी प्रवृत्ति और कोई अनियमितता होने पर संभावित कारणों को प्रकट करेगी। दोनों ही मामलों में, स्थिति को प्रबंधक एस. आई. बी. या बी. एम. के ध्यान में लाया जाता है, जिनसे हर महीने इन विवरणों की जांच करने की अपेक्षा की जाएगी। फॉर्म एस. आई. एफ. 6 पर टिप्पणियों के मद 6 में असामान्यता संकेत (एस. आई. सी.) उदाहरणात्मक हैं। अन्य असामान्यताएँ भी हो सकती हैं जिनका अनुमान इस रूप के आधार पर लगाया जा सकता है। श्री कृष्णमूर्ति उराला-पीडब्लू 4 ने कार्यवाही के पृष्ठ 10, 11 पर बयान दिया कि आरोपित अधिकारी ने कोई आवधिक निरीक्षण नहीं किया है। यह अभिसाक्ष्य उपरोक्त आरोप को स्पष्ट रूप से साबित करता है।

तदनुसार, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि आवधिक निरीक्षण के संचालन के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पर्याप्त रूप से साबित हुए हैं।”

(फाइंडिंग्स के सारांश में 'I' को फील्ड ऑफिसर को इंगित करने के रूप में दर्ज किया गया है)

इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिपोर्ट में लिखा है कि बचाव पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है कि "उनके द्वारा निरीक्षण किए गए हैं"। खुद को संतुष्ट करने के लिए, क्या गलती से कर्मचारी पर जिम्मेदारी स्थानांतरित की गई है, हमने पीडब्लू-4 कृष्णमूर्ति उराला के साक्ष्य का अध्ययन किया जिनके पास

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

श्री संजय कपूर, विद्वान वकील और श्री एस. एन. भट, विद्वान वरिष्ठ वकील दोनों द्वारा अभिसाक्ष्य, प्रचुर संदर्भ दिए गए थे।

20. आरोप ज्ञापन में, प्रत्यर्थी पर विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थी ने शाखा प्रबंधक से मंजूरी की सिफारिश की थी और प्राप्त की थी, विभिन्न इकाइयों को क्रेडिट सीमाएं जैसा कि उसमें विस्तृत है और निरंतर आधार पर अतिरिक्त आहरण की अनुमति दी थी और प्रत्यर्थी ने नियंत्रक को अतिरिक्त आहरण की सूचना नहीं दी थी और मौजूदा निर्देशों के अनुसार आवधिक निरीक्षण नहीं किया था। आरोप पत्र में इस आरोप की पुष्टि करने के लिए कई इकाइयों का उल्लेख किया गया था कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार, उन पर आवधिक निरीक्षण नहीं किए गए थे। पीडब्लू-4 के अभिसाक्ष्य में निम्नलिखित बातें सामने आई हैं- श्री कृष्णमूर्ति उराला ने 17.02.1993 पर दर्ज किया है:

“पीओ: श्री उराला, क्या आप संयोग से जानते हैं कि जून 86 से 1988 के बीच इस इकाई को संभालने वाले वरिष्ठ अधिकारी कौन थे।

पीडब्लू4:हां. यह श्री ए. जी. डी. रेड्डी हैं।.....

पीडब्लू4:निर्धारित निर्देशों के अनुसार इकाइयों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया क्या है।

पीओ:निर्धारित निर्देश यह है कि इकाई का सामान्य रूप से महीने में एक बार एफ. ओ. द्वारा स्टॉक स्टेटमेंट के साथ निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि ए./सी. एस. से धन के वितरण का उचित उपयोग किया गया है या नहीं।

वित्तीय अधिकारी को शाखा निरीक्षण पुस्तक इकाइयों में ले जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियाँ लिखनी चाहिए, और उसे इकाई में रखी निरीक्षण पुस्तक में टिप्पणियाँ भी करनी चाहिए।”

पीओ:इन इकाइयों के लिए निरीक्षण किए गए थे।पीडब्लू4:नहीं "।

03.03.1993 पर पूछताछ में अभिसाक्ष्य पीडब्लू-4 का बयान:

“डी आर:आपने कहा कि कुछ इकाइयों का आपके पूर्ववर्तियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। क्या आप हमें इस आरोप का आधार बता सकते हैं?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी [के. वी. विश्वनाथन, जे.]

665

[के. वी. विश्वनाथन, जे.] 666

अभि. साक्षी 4:कोई उचित अभिलेख नहीं रखा गया था।

डी आर:क्या आपने 1988,87 और उससे पहले की अवधि से संबंधित निरीक्षण कार्डों का पता लगाया/देखा है?

पीडब्लू4:हां.

डी आर:ई. ओ. को प्रस्तुतिकरण:हमें शाखा द्वारा बताया गया है कि 88,87 और पीछे से संबंधित निरीक्षण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।कृपया अभियोजन पक्ष को बचाव उद्देश्य के लिए अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दें।ईओ:डी. आर. निर्दिष्ट रूप से आर/ओ में निरीक्षण रजिस्टरों का उल्लेख करता है कि आपको अपने अनुरोध की जांच करने के लिए ई. ओ. को सक्षम करने के लिए किन इकाइयों की आवश्यकता है।डी आर:आरोप पत्र में उल्लिखित आर/ओ इकाइयों में निरीक्षण कार्ड।

ईओ:पी. ओ. डी. आर. के अनुरोध की जांच कर सकता है और यदि संभव हो तो रिकॉर्ड, यदि उपलब्ध हो, दिया जा सकता है।

अन्यथा ईओ को एक रिपोर्ट दी जा सकती है।

21. यह स्पष्ट करता है कि आरोप पत्र में उल्लिखित इकाइयों से संबंधित निरीक्षण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश था। निम्नलिखित जाँच कार्यवाही में प्रतिलेख में पाया जाता है (दिनांक 04.05.1993):- “पीओ:पिछली बैठक में डी. आर. ने मुझसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। संबंधित अवधि के लिए निरीक्षण रजिस्टर और आर/ओ मेसर्स बिंदु एंटरप्राइजेज में मशीनरी की सूची। मैं ई. ओ. और डी. आर. के अवलोकन के लिए अनुरोध के अनुसार निरीक्षण रजिस्टर और मशीनरी की एक सूची भी जमा कर रहा हूँ।

डी आर: हम उक्त दस्तावेजों को देखने के बाद जवाब देंगे।” (जोर दिया गया)

सबूत की जिम्मेदारी

22. उपरोक्त पर विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश हैं कि बैंक का प्रभार, कि निरीक्षण नहीं किया गया था, स्थापित हो गया था। फिर यह प्रत्यर्थी को दिखाना था, जैसा कि उसने किया था, आरोप पर उसकी प्रतिक्रिया क्या थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

23. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में, सबूत के बोझ का सवाल आरोप की प्रकृति और प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किसी दिए गए मामले में, स्पष्टीकरण के आधार पर बोझ प्रत्यर्थी को स्थानांतरित किया जा सकता है। [उड़ीसा देखें।

खनन निगम और एक अन्य बनाम आनंद चंद्र पृष्टि, (1996) 11

एस. सी. सी. 600, पैरा 6] 24. यहाँ निर्दिष्ट प्रभार नामित इकाइयों की एक श्रृंखला के संबंध में था, आवधिक निरीक्षण नहीं किए गए थे। आरोप का समर्थन करने के लिए, गवाहों से पूछताछ की गई और उनके बचाव प्रतिनिधि के माध्यम से अनुरोध पर, पूछताछ अधिकारी ने प्रस्तुत अधिकारी को निरीक्षण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पूछताछ कार्यालय ने विशेष रूप से रक्षा प्रतिनिधि से उन इकाइयों के संबंध में निरीक्षण रजिस्ट्रों का उल्लेख करने के लिए कहा जो आवश्यक हैं। रक्षा प्रतिनिधि विशेष रूप से आरोप पत्र में उल्लिखित इकाइयों के संबंध में निरीक्षण रिकॉर्ड के लिए अनुरोध करता है। पूछताछ कार्यालय प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अनुरोध की जांच करने का निर्देश देता है और यदि उपलब्ध हो तो अभिलेख दिए जाते हैं। इसके बाद, यह रिकॉर्ड में आया है कि प्रस्तुतकर्ता कार्यालय ने पूछताछ कार्यालय और रक्षा प्रतिनिधि के अवलोकन के लिए प्रासंगिक अवधि के लिए निरीक्षण रजिस्टर प्रस्तुत किया। इस पर बचाव पक्ष के प्रतिनिधि ने कहा कि वे दस्तावेजों को देखने के बाद जवाब देंगे। एफ. आई. के नेतृत्व में लिखित प्रस्तुतियों में, एक शिकायत उठाई जाती है कि निरीक्षण से संबंधित अभिलेख जांच के अंतिम चरण में प्रस्तुत किए गए थे। हम प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि यह निरीक्षण रजिस्टर के प्रस्तुत होने के बाद था कि प्रत्यर्थी के बचाव प्रतिनिधि ने कहा था कि वे उक्त

दस्तावेजों को देखने के बाद जवाब देंगे।आगे कोई जवाब नहीं आया।न तो अभिलेखों से और न ही सुनवाई में यह प्रदर्शित किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा निरीक्षण करने में विफलता के आरोप का विरोध कैसे किया गया था।जिन अभिलेखों को उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, उनकी जिम्मेदारी प्रत्यर्थी पर स्थानांतरित कर दी गई ताकि यह दिखाया जा सके कि आरोप असमर्थनीय था।25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से प्रथम आरोप के प्रथम अंग के संबंध में, अर्थात् आवधिक निरीक्षण करने में विफलता के संबंध में, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूछताछ कार्यालय की जांच साक्ष्य के गलत अध्ययन पर है या कि इकाइयों के निरीक्षण के रिकॉर्ड उन रिकॉर्डों का हिस्सा थे जो संभवतः गलत हो सकते हैं या एक जांच किसी आवारा वाक्य पर आधारित थी और व्यक्तिगत ज्ञान को पूछताछ कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड में आयात किया गया था।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 668

667

न्यायसंगत बंधक के निर्माण के लिए औपचारिकताओं के संबंध में प्रभार

26. एक अन्य पहलू है जो विद्वान एकल न्यायाधीश और परिणामस्वरूप खंड पीठ के ध्यान से पूरी तरह से छूट गया है।पूछताछ कार्यालय द्वारा निपटाए गए आरोपों में से एक एक न्यायसंगत बंधक का निर्माण करके मेसर्स सरस्वती फैब्रिकेटर्स को अग्रिम राशि हासिल नहीं करने के बारे में था, भले ही अचल संपत्ति का न्यायसंगत बंधक पक्ष द्वारा दिया गया था।इन्क्वायरी ऑफिसर द्वारा निम्नलिखित तथ्य दर्ज किए गए थे:-

“पी. ई. एक्स. 9 के पृष्ठ 12 पैरा 7.2 पर, उधारकर्ता ने 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 458, विवेकनगर, बेंगलूर में इमारत का समान गिरवी रखा है।और 700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया गया।श्री के. वी. श्रीनिवासन से संबंधित फुट जिसका मूल्य रु। 4. 5 लाख।सी. ओ. ने अपनी लापरवाही से बी. एम. को अपनी सिफारिशों में यह निर्धारित नहीं किया है। इस प्रक्रिया में न्यायसंगत बंधक के गैर-निर्माण द्वारा अग्रिम को संपार्श्विक रूप से सुरक्षित नहीं किया जा सकता था।इसलिए यह आरोप साबित होता है कि न्यायसंगत बंधक नहीं बनाया गया है।”

27. स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, हमने इस मुद्दे पर जांच कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच की। 17.02.1993 पर जाँच कार्यवाही में दर्ज पीडब्लू-4 के अभिसाक्ष्य में निम्नलिखित पाया गया है:-

“पीओ:पी. ई. एक्स. 9 के पी. ई. एक्स. पृष्ठ 12 आइटम 7.2 को देखते हुए कृपया हमें इकाई द्वारा दी गई संपार्श्विक प्रतिभूति बताएँ।

पीडब्लू4:.....सुरक्षा एक ऐसी जगह है जिसका माप 1,500 वर्ग मीटर है।फीट. और बी. एल. डी. जी.इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग किलोमीटर है।विवेक नगर, बेंगलूर में श्री के. वी. श्रीनिवासन से संबंधित फुट की कीमत रु। 4. 5 लाख।

पीओ:क्या इस ऋण की मंजूरी के समय औपचारिकता पूरी हो गई थी?

पीडब्लू4:नहीं "।

03.03.1993 पर दर्ज पीडब्लू-4 का अभिसाक्ष्य-

“डी आर:ऋण की मंजूरी में कौन शर्तें लगाता है?शाखा स्तर पर?

पीडब्लू4:बी. आर. के परामर्श से फील्ड कार्यालय। प्रबंधक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

डी आर:क्या बी. आर. प्रबंधक मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के रूप में किसी भी शर्त को माफ कर सकता है?

पीडब्लू4:यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।.....

डी आर:pg से PEX9 दिखाया जा रहा है।एल से 12 आवेदन का गठन करते हैं।क्या आप सहमत हैं?

पीडब्लू4:यह आवेदन सह साक्षात्कार प्रपत्र है।

डी आर:पीजी से।13 19 रूपों का मूल्यांकन ज्ञापन।पीडब्लू4:हां.

डी आर:आवेदन में आवेदक के नाम शामिल हैं और मूल्यांकन में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मंजूरी की शर्तें शामिल हैं।क्या आप सहमत हैं?

पीडब्लू4:आवेदन सह साक्षात्कार प्रपत्र में संभावित उधारकर्ता के बारे में जानकारी होती है।

जानकारी के आधार पर बी. एम. के परामर्श से एफ. ओ. को मूल्यांकन ज्ञापन में क्रेडिट सीमा और शर्तों को निर्धारित करना होता है।

डी आर:पृष्ठ 12 पैरा 7 पर। 2 हालांकि एक ऑफ एर है, pg पर।18 पैरा 9.2 अधिनियम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आवेदक के ऋण को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लिया जाना चाहिए। क्या आप देखते हैं?पीडब्लू4:में नहीं जानता।

डी आर:pg पर।12 पैरा 7.2 में कुछ संपत्तियों के न्यायसंगत बंधक का उल्लेख है।क्या आप देखते हैं?

पीडब्लू4:हां.

डी आर:pg पर।18 पैरा 9.2 शर्तक अन्तर्गत शर्त स्तम्भ खाली अछि।क्या आप देखते हैं?

पीडब्लू4:हां.

डी आर:कुछ प्रतिभूतियों का न्यायसंगत बंधक लेना मंजूरी देने वाले अधिकारियों यानी पी. ई. एक्स. 9, पी. जी. में शाखा स्तर पर बी. एम. द्वारा निर्धारित शर्त नहीं है।¹⁸, पैरा 9.2 'शर्त'।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 670

669

पीडब्लू4:हां,

डी आर:इसलिए गैर-मौजूद शर्तों की औपचारिकताओं को पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता है।क्या आप देखते हैं?

पीडब्लू4:में नहीं जानता।”

28. ध्यान देने योग्य बात यह नहीं है कि पी. ई. एक्स. 9 मूल्यांकन ज्ञापन के साथ मेसर्स सरस्वती फैब्रिकेटर के संबंध में कार्यशील पूंजी के लिए आवेदन से संबंधित है। अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ऋण के लिए आवेदक के पास भूमि और भवन के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति थी और संपार्श्विक प्रतिभूति की औपचारिकता नहीं ली गई थी। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह शाखा प्रबंधक के परामर्श से क्षेत्र अधिकारी है जिसे ऋण सीमा और शर्तों को निर्धारित करना होता है। अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि मेसर्स सरस्वती फैब्रिकेटर्स के संबंध में इस प्रकार उल्लिखित न्यायसंगत बंधक के संबंध में कोई शर्त नहीं रखी गई थी, भले ही पक्ष ने अचल संपत्ति के रूप में न्यायसंगत संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान की थी।

29. प्रत्यर्थी का स्पष्टीकरण केवल यह है कि संपार्श्विक प्रतिभूति लेने के संबंध में मंजूरी आदेश में कोई शर्त नहीं थी। आरोप यह है कि मेसर्स सरस्वती फैब्रिकेटर्स के संबंध में, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक बनाने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। पीडब्लू-4 का प्रमाण यह है कि संपार्श्विक सुरक्षा के लिए शर्त शाखा प्रबंधक के परामर्श से क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है।

30. उपरोक्त के आलोक में, पूछताछ कार्यालय का यह कहना कि प्रत्यर्थी ने अपनी लापरवाही से शाखा प्रबंधक को अपनी सिफारिश में यह निर्धारित नहीं किया था और इस तरह, न्यायसंगत बंधक के निर्माण द्वारा अग्रिम को संपार्श्विक रूप से सुरक्षित नहीं किया जा सकता था, विकृत या बिना किसी सबूत के नहीं कहा जा सकता है।

31. रिट याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया जवाब कि व्यक्तिगत गारंटी उपलब्ध थी; कि मंजूरी में संपत्ति के न्यायसंगत बंधक के संबंध में कोई शर्त नहीं थी; कि स्वामित्व के दस्तावेजों का पता केवल सितंबर, 1988 में लगाया गया था, जब उसने जून, 1988 में शाखा छोड़ी थी; कि प्रत्यर्थी के उत्तराधिकारी और तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा आवश्यक के अनुसार, प्रत्यर्थी ने दस्तावेजों की पहचान की थी और सुझाव दिया था कि वे न्यायसंगत बंधक के निर्माण से जुड़े काम को पूरा करते हैं, ऐसे मामले नहीं हैं जिन पर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विचार है।

[2023] 11 एस सी आर।

प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दाखिल की गई लिखित प्रस्तुतियों में, प्रत्यर्थी का दावा है कि, कागजात का पता लगाने के बाद, वास्तव में, बंधक को समाप्त कर दिया गया था। यहां तक कि इससे भी अभिलिखित आरोपों और तथ्यों में कोई अंतर नहीं आएगा, जो स्वयं अभिलिखित साक्ष्य पर आधारित थे।

अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में न्यायिक समीक्षा का दायरा

32. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश और नियुक्ति प्राधिकरण का आदेश किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या विकृत हैं। यहां तक कि अगर हम नियंत्रण प्रपत्र जमा न करने, संचालन के क्षेत्र के उल्लंघन और अचल संपत्ति की घोषणा न करने और कुछ अन्य आरोपों के संबंध में रिपोर्ट को छोड़ देते हैं, तो भी जुर्माने का आदेश कायम रखा जा सकता है।

33. जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है, समय-समय पर निरीक्षण करने में विफलता और मेसर्स सरस्वती फैब्रिकेटर के मामले में अचल संपत्ति को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लेने के लिए निर्धारित नहीं करने में लापरवाही के पहलू, पक्ष द्वारा इसे रद्द करने के बावजूद, हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए विवश करते हैं कि दंड का आदेश पारित करने के लिए अपीलार्थी के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री थी। 34. श्री एस. एन. भट, विद्वान वरिष्ठ वकील, निर्णयों पर भरोसा करते हुए

नंद किशोर प्रसाद न्यायालय बिहार राज्य और अन्य, (1978) 3 एस. सी. सी. 366 और अनिल कुमार न्यायालय पीठासीन अधिकारी और अन्य, (1985) 3 एस. सी. सी.

378 यह तर्क दिया जाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को कुछ साक्ष्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, जिसमें कुछ हद तक अवहेलना होनी चाहिए जो उसके खिलाफ आरोप के संबंध में अपराधी के अपराध की ओर इशारा करती है। उन्होंने तर्क दिया कि संदेह को सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्दोष लोगों को केवल पूछताछ कार्यालय के निर्देश के आधार पर अपराध दर्ज करके दंडित नहीं किया जाता है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले की ओर आकर्षित हैं। उद्धृत निर्णय स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य हैं, उन कारणों के लिए जो हमने वर्तमान मामले के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए ऊपर दिए हैं।

35. श्री संजय कपूर, बैंक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य पर निर्भर हैं

बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम लाल भास्कर और एक अन्य, (2011) 10 एस. सी. सी. 249।
में।

उस फैसले में विभागीय कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा का दायरा 671 था

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी [के. वी. विश्वनाथन, जे.] 672

ए. पी. बनाम राज्य में निर्धारित और निर्धारित सिद्धांत एस. श्री रामाराव, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1723 को दोहराया गया था, जो इस प्रकार है:-

“इस न्यायालय ने ए. पी. राज्य और अन्य बनाम एस. श्री रामाराव (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1723, पैरा 7) में निर्णय दिया है:

“7. ... संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक लोक सेवक के खिलाफ विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों के फैसले पर उच्च न्यायालय का गठन नहीं किया गया है: यह निर्धारित करने के लिए संबंधित है कि क्या जांच उस ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है, और उस ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, और क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। जहां कुछ साक्ष्य है, जिसे जांच करने के कर्तव्य के साथ सौंपा गया प्राधिकरण स्वीकार कर चुका है और कौन से साक्ष्य इस निष्कर्ष का उचित रूप से समर्थन कर सकते हैं कि अपराधी अधिकारी आरोप का दोषी है, तो यह उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के लिए याचिका में साक्ष्य की समीक्षा करे और साक्ष्य पर एक स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचे।”

13. इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकरण के कार्यों पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठता है और जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के कार्यों को कुछ साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया जाता है, तब तक उच्च न्यायालय साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं करता है और साक्ष्य पर एक अलग और स्वतंत्र निर्णय पर नहीं आता है। इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में कानून की इस स्थिति को दोहराया गया है, जिसे हमें संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी विवादित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की फिर से सराहना की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जांच कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री और प्रत्यर्थी नं. 1 यह किसी भी कदाचार का गठन नहीं करता है और प्रत्यर्थी नहीं। 1 किसी भी दुरुपयोग का दोषी नहीं था।”

36. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि विभागीय जांच कार्यवाही के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। यह अपील की प्रकृति में नहीं है और निर्णय के गुण-दोष पर समीक्षा की अनुमति नहीं है। जांच का दायरा यह जांचना है कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया वैध है और यह सुनिश्चित करना है कि तथ्य किसी भी सबूत से वंचित नहीं हैं। यदि अभिलेखों से पता चलता है कि तथ्य कुछ पर आधारित हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

साक्ष्य, न्यायिक समीक्षा में यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह उसी की पुनः सराहना करे और साक्ष्य पर एक स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचे। इस लक्ष्मण रेखा को इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी कतार में मान्यता दी गई है और दोहराया गया है।

37. वर्तमान मामले में, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि रिपोर्ट किसी सबूत पर आधारित नहीं है या यह विकृत है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने जाँच कार्यवाही और लगाई गई सजा को दरकिनार करते हुए न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का उल्लंघन विद्वान डिबीजन बेंच ने एक संक्षिप्त आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के एक हिस्से को निकालने के बाद, यह निर्णय दिया है कि जांच के रिकॉर्ड को देखने के बाद वे यह नहीं मानते हैं कि आरोपों को किसी भी तरह से विशिष्ट शहर में निपटाया गया है। इसके बाद वे निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश को इसके निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायसंगत ठहराया गया था। हम विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेशों को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं।

शुल्कों की गंभीरता

38. जो सवाल बचा है, वह यह है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, क्या लगाए गए दंड के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

39. कानून अच्छी तरह से तय है कि यदि किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में, साबित किए गए आरोपों पर दंड का आदेश लगाया जा सकता है और लगाया गया दंड उन आरोपों पर कानूनी रूप से टिकाऊ है, तो यह न्यायालय के लिए इस बात पर विचार करने के लिए नहीं है कि क्या केवल उन आधारों ने सजा देने के अधिकार के साथ वजन किया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर, आरोप के कुछ पहलुओं पर, सबूत की कमी पाई गई होगी। हालाँकि, चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपास्त करना कानून यह है कि जब तक दी गई सजा केवल उन आरोपों में से किसी के साथ सह-संबंधित नहीं है जो साबित नहीं हुए हैं, तब तक दंड को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में सजा तब भी कायम रखी जा सकती है जब साबित नहीं किए गए आरोपों को अलग कर दिया जाए। [उड़ीसा राज्य बनाम बिद्याभूषण महापात्रा [1963] पूरक देखें। 1 एस. सी. आर. 648 और डिप्टी जनरल

प्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) और अन्य। बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव,

(2021) 2 एससीसी 612]। 40. फिर एकमात्र सवाल यह है कि क्या लगाया गया जुर्माना अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है? मौखिक दलीलों के साथ-साथ लिखित प्रस्तुतियों में, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि वित्तीय गबन या बैंक को कोई वित्तीय नुकसान पहुंचाने का कोई आरोप नहीं था।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए. जी. डी. रेड्डी [के. वी. विश्वनाथन, जे.]

इस प्रस्तुतिकरण का प्रतिवाद अपीलार्थी द्वारा इस पर निर्भरता रखते हुए किया गया था -

अनुशासनिक प्राधिकरण-सह-क्षेत्रीय प्रबंधक में इस न्यायालय का निर्णय

और अन्य बनाम निकुंजा बिहारी पटनायक, (1996) 9 एस. सी. सी. 69, विशेष रूप से, न्यायालय का उसके पैरा सात में यह तर्क देने के लिए अभिनिर्धारित करना कि परीक्षण वास्तव में नुकसान का परिणाम नहीं है या लाभ नहीं हुआ है। परीक्षण यह है कि क्या अपराधी कर्मचारी ने बैंक के निर्धारित मानदंडों का पालन किया है। इस मामले में लगाया गया जुर्माना भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियमों के नियम 49 (ई) के तहत परिकल्पित "स्केल-1 में सबसे निचले स्तर तक मूल वेतन में कमी" है और इसके अलावा, दोषी अधिकारी द्वारा 18.08.1990 से उसकी बहाली की तारीख तक निलंबन के तहत बिताई गई अवधि को केवल निलंबन के रूप में माना जाता है। चूंकि समय-समय पर निरीक्षण नहीं करने का आरोप और मेसर्स सरस्वती फैब्रिकेटर के संबंध में न्यायसंगत बंधक बनाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में विफलता साक्ष्य द्वारा समर्थित है, इसलिए हम नहीं मानते कि लगाया गया जुर्माना असमान है ताकि न्यायालय की अंतरात्मा को झटका लगे। हम नियुक्ति प्राधिकरण के दिनांक 31.01.1995 के आदेश में लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखते हैं और जैसा कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है।

41. ऊपर बताए गए कारणों से, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने रिट याचिका को अनुमति देने और पूछताछ कार्यालय के निर्णय, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय, नियुक्ति प्राधिकरण के आदेश और अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती की थी। इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेश को अपास्त करनाते हैं और प्रत्यर्थी के नेतृत्व में 1997 की रिट याचिका संख्या 29547 को खारिज करते हैं। तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन